भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5498

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए ग्रिड प्रबंधन</u>

5498. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय ग्रिड में निर्वाध एकीकरण के लिए संचरण अवसंरचना तथा ग्रिड प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु कोई विशेष रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में गत पांच वर्षों के दौरान स्थापित और वर्तमान में ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, लघु जलविद्युत और जैव ईंधन सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत ओडिशा में ग्रिड एकीकरण, ट्रांसमिशन सुदृढ़ीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा निकासी अवसंरचना के लिए सरकार द्वारा किए गए बजटीय आवंटन, जारी धनराशि और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ओडिशा में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को सुगम बनाने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों तथा अंतर्राज्यीय संचरण लाइनों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) के अनुसार, भारत भर के नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) समृद्ध राज्यों से नवीकरणीय विद्युत की आपूर्ति के लिए ओडिशा सहित पूर्वी ग्रिड में इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) नेटवर्क को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है।

इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III योजना के अंतर्गत ओडिशा द्वारा 1.7 गीगावॉट आरई की निकासी के लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएनएसटीएस) नेटवर्क का प्रस्ताव है।

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान फरवरी, 2026 तक ओडिशा राज्य में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विवरण इस प्रकार है:

लघु जल विद्युत	पवन विद्युत	जैव (बायो) विद्युत	सौर विद्युत	बड़ी जल विद्युत	कुल क्षमता
(MW)	(MW)	(MW)	(MW)	(MW)	(MW)
76.01	0.00	5.00	359.04	12.30	452.35

(ग) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत ओडिशा में ग्रिड एकीकरण, पारेषण सुदृढ़ीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा निकासी अवसंरचना के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कोई निधियां आवंटित, जारी या व्यय नहीं की गई हैं।

(घ) देश में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने जून, 2025 में पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) के माध्यम से 5,400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 30 गीगावाट घंटे बीईएसएस क्षमता के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, ओडिशा राज्य को 18 लाख रुपये प्रति मेगावाट घंटे की दर से वीजीएफ प्रदान करते हुए 500 मेगावाट घंटे बीईएसएस क्षमता आवंटित की गई है।

****